

Inflationary Gap

Inflationary gap की व्याख्या का प्रतिपादन 1940 में सर्वप्रथम J.M. Keynes ने अपनी पुस्तक 'How to pay for the War' में किया था। Keynes का मत था कि अर्थव्यवस्था अगर पूर्ण रोजगार के अवसर के स्तर पर कार्यरत है और अर्थव्यवस्था में सम्पूर्ण मौद्रिक मांग बढ़ जाए और उत्पादन पूर्ववत् रहे तो Inflationary gap का जन्म होता है। इस व्याख्या की किंग परिभाषा उनी ने

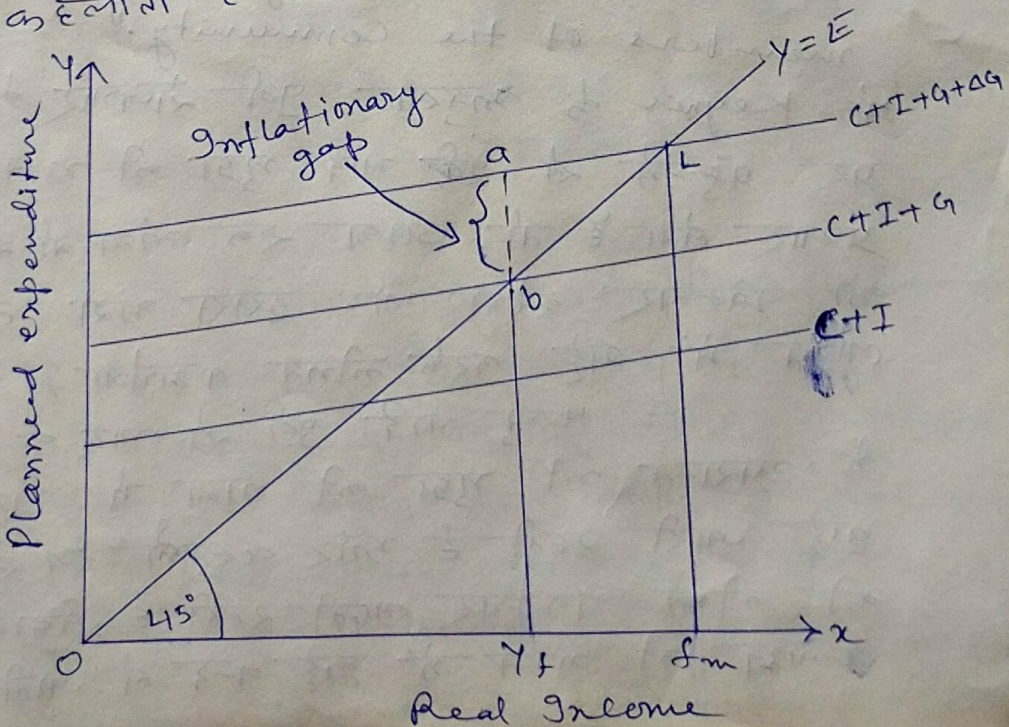
"Inflationary Gap is defined as the amount of the government expenditure against which there is no corresponding increase of real resources of man power or material by some other members of the community."

श्री J.M. Keynes के अनुसार पूर्ण रोजगार के बिंदु पर पहुँचने से पूर्व यदि मुद्रा की मात्रा का प्रसार होता है तो अतः एक अंश ही रोजगार का विस्तार करता और दूसरा अंश उत्पादन-लागत में वृद्धि करके कीमत बढ़ावेगा।

परन्तु यदि पूर्ण रोजगार के बिंदु के उपरान्त ही मुद्रा की मात्रा में होने वाली वृद्धि जारी रहती है और वस्तुओं एवं सेवाओं की कीमतें गिरती बढ़ती रहती हैं जबकि उत्पादन की मात्रा में वृद्धि कम हो जाती है।

इसी कीमत में बतने वाले अन्तर को
Inflationary gap कहते हैं।

जब किसी देश में मुद्रा की मात्रा बढ़ती है तब लोगों की मौद्रिक आग्रही भी बढ़ जाती है। मौद्रिक आग्रही के बढ़ जाने के फलस्वरूप लोगों का व्यय भी बढ़ जाता है इससे कीमतों में उपर बढ़ने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है। यदि व्यय योग्य मौद्रिक आग्रही तथा वस्तुओं और सेवाओं की इच्छा दोनों एक ही अनुपात में बढ़ते हैं तो कीमत-स्तर में वृद्धि नहीं हो सकती। इसके विपरीत यदि वस्तुओं और सेवाओं की तुलना में यदि व्यय योग्य मौद्रिक आग्रही अधिक अनुपात में बढ़ती है तो कीमत-स्तर अवश्य ही बढ़ेगा। यही कीमत में अन्तर 'कीमती अन्तर' कहलाता है। इसे किन्हीं चित्र से स्पष्ट कर सकते हैं।



उपरोक्त चित्र में वास्तविक आय को Ox तथा मिलापित आय को Oy रेखा पर मापा जाता है। 45° की OL रेखा आय तथा व्यय के बीच संतुलन को दिखाती है। $C+I$ रेखा पर उपभोग और तथा विनिर्माण, $C+I+G$ रेखा द्वारा उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय और $C+I+G+\Delta G$ द्वारा उपभोग, निवेश, सरकारी व्यय एवं वही हुई सरकारी व्यय को व्यक्त करता है। आय के Y_1 स्तर पर उपभोग, निवेश तथा सरकारी व्यय ($C+I+G$) की रेखा P बिंदु पर पूर्ण रोजगार की स्थिति में है। अतः आय एवं व्यय संतुलित अवस्था में है और $G.G.$ की मात्रा शून्य है। अब यदि सरकारी व्यय में ΔG के बराबर वृद्धि की जाती है तो संतुलन बनाने के लिए वास्तविक आय Y_1 से Y_2 बढ़कर Y_2 हो जाता है। यहाँ $C+I+G$ तथा $C+I+G+\Delta G$ रेखा के अन्तर (a-b) स्थैतिक अन्तर को दर्शाता है।

विभिन्न मर्चशास्त्रियों ने Inflationary

gap की धारणा की आलोचना की है -

- ① प्रो. Hansen के अनुसार किन्स ने स्फीतिक अन्तराल को केवल वस्तु बाजार से संबंधित किया है तथा साध्य बाजार की अवहेलना की है। जबकि $G.G.$ वस्तु बाजार के साथ ही साध्य

बाजार में अतिरिक्त मांग के कारण उत्पन्न होता है।

② प्रो. कूपमैन्स के अनुसार 9.6 Static analysis से सम्बंधित है जबकि inflation की स्थितियों प्रकृति से dynamic होती है।

③ 9.6 इस गान्यता पर आधारित है कि पूर्ण रोजगार स्तर की कीमतों में वृद्धि होती है अर्थात् अतिरिक्त मांग की कीमतों पर सीधा प्रभाव पड़ता है। जबकि कीमतों बढ़ने से लागत की मात्रा बढ़ जाती है अर्थात् 9.6 अतिरिक्त मांग स्थिति से व लागत स्थिति से सम्बंधित है। अतः यहाँ मजदूरी की स्थिति पेश होती है।

④ Inflationary gap केवल प्रवाह की कारण से सम्बंधित है - जैसे चालू लागत से व लाभ, उपभोग से व बचत इत्यादि किन्तु पूर्ण रोजगार स्तर पर कीमतों में होने वाली वृद्धि का प्रभाव वस्तुओं के स्टाक पर भी पड़ता है।

Bridge up or Control of Inflationary gap

Next Page Part - II में है

Sandhya Rai
Dept of Economics